दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 09 दिसंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 72

महत्वपूर्ण एवं खास

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का महिलाओ के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी

लखनऊ (आरएनएस)। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्राहमने एक महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने महिला घोषणापत्र को छह हिस्सों में बांटा है, स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। हमने घोषणापत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति होगी ।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई पेरशानी

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बुधवार को भी शीत लहर जारी रही और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के मैदानी इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़ों से बर्फीली हवाएं चलीं। मौसम विभाग (एमईटी) के एक अधिकारी ने कहा कि बुधवार को घाटी और लद्दाख क्षेत्र में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु (फ्रीजिंग प्वाइंट)से एक डिग्री नीचे रहा। बुधवार को न्यूनतम तापमान श्रीनगर में माइनस 0.4, पहलगाम में माइनस 3.4 और गुलमर्ग में माइनस 6.0 है। लद्दाख के द्रास शहर में रात का न्यूनतम तापमान शून्य से 14.5 नीचे, लेह में शून्य से 8.7 नीचे और कारगिल में शून्य से 6.8 नीचे दर्ज किया गया। मौसम अधिकारी ने कहा, जम्मू शहर और कटरा, दोनों में 8.7, बटोटे में 3.9, बनिहाल में 2.6 और भद्रवाह में 2.5 न्यूनतम तापमान रहा जबकि रात में आसमान साफ रहने के कारण आने वाले दिनों में शीत लहर की स्थिति बढ़ने की संभावना है।

1 मिनट में बिना दर्द के मौत, सरकार ने मौत की मशीन को दी कानूनी मंजूरी

बर्न । स्विट्जरलैंड सरकार ने सुसाइड मशीन के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस मशीन से किसी भी व्यक्ति की 1 मिनट के भीतर बिना किसी दर्द के मौत हो सकती है। ये मशीन ताबूत के आकार की बनी हुई है। इस मशीन के जरिए ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कर दिया जाता है जिससे 1 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। एग्जिट इंटरनेशनल नाम की संस्था के डायरेक्टर डॉ. फिलिप निट्स्के ने इस मौत की मशीन को बनाया है। उन्हें डॉ. डेथ भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता मिली हुई है। एग्जिट इंटरनेशनल का दावा है कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में 1,300 लोगों ने दूसरों की मदद से आत्महत्या की थी। कहा जा रहा है कि इस मशीन को ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो बीमारी की वजह से हिल-डुल भी नहीं पाते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मशीन को अंदर से भी ऑपरेट भी किया जा सकता है। बीमार व्यक्ति मशीन के अंदर पलकें झपकाकर भी इस मशीन को चला सकता है। इस मशीन में बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल लगा है जिसे ताबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

नासा के मिशन के लिए चुना गया भारतीय मूल का डॉक्टर

न्यूयॉर्क। नासा ने निकट भविष्य के अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए 10 नए नामों की घोषणा की है, जिनमें एक भारतीय मूल के डॉक्टर भी शामिल हैं. ये लोग चांद और मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशनों का हिस्सा बनेंगे.45 वर्षीय डॉक्टर अनिल मेनन स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे. उसके पहले वो नासा के लिए भी इसी भूमिका में अंतरिक्ष मिशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल कर चुके हैं. वो इससे भी चार बार आवेदन कर चुके थे. उनका पांचवां आवेदन सफल रहा. अनिल के माता पिता भारत और यूक्रेन से अमेरिका जा कर बस गए थे. अनिल का जन्म अमेरिका में ही हुआ और वो वहीं पले बढ़े. उन्हें आपात स्थितियों में भी काम करने का अनुभव है. 2010 में उन्होंने हैती में आये विध्वंसकारी भूकंप के बाद पीड़ित लोगों की मदद की थी.

नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत

हेलिकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी की भी हुई मौत, 14 में से 13 की गई जान

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज हुए हेलिकॉप्टर हादसे में उनकी, पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य अफसरों और सहयोगियों के साथ मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की पुष्टि की है। हादसे में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की ही जान बची है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वायुसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, बहुत ही अफोसस के साथ अब इसकी पुष्टि हुई है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य की मृत्यु हो गई है। रावत के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित

शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जाहिर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रावत के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए उनके कामकाज की तारीफ की है और उन्हें बहादुर सैनिक और सच्चा देशभक्त बताया।

जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का एक हेलिकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह हादसा कोहरे और खराब मौसम की वजह से वायुसेना का एमआई-17वीएच हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर ने कोयंबटूर के पास सुलुर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी। हेलिकॉप्टर के गिरते ही इसमें आग लग गई। दुर्घटनास्थल पर भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर के क्षतिग्रस्त और जले हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने तेज आवाज सुनी, जाहिर तौर पर हादसे की आवाज थी, और बाद में हेलिकॉप्टर में आग लगी, जिसमें उसमें सवार लोग झुलस गए। आग में जल जाने की वजह से शवों की डीएनए जांच भी कराई जाएगी। सीडीएस जनरल रावत वेलिंग्टन में डिफेंस सर्विसेज कॉलेज (डीएससी) जा रहे थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर कोयंबटूर के सुलुर से वेलिंग्टन में डीएससी की ओर जा रहा था, जहां जनरल रावत, थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे के साथ बाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे।

हेलिकॉप्टर हादसे में कैप्टन वरुण सिंह ही बचे, अस्पताल में चल रहा है इलाज

तमिलनाडु के कुन्नूर में सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अफसरों की मौत हो गई है। इस हादसे में सिर्फ एक सैन्य अधिकारी कैप्टन वरुण सिंह हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो गंभीर रूप से घायल हैं। कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। भारतीय वायु सेना ने बुधवार को कुन्नूर विमान हादसे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। सेना के मुताबिक, भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कुन्नूर में सेना विमान हादसे में घायल हुए हैं। उनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सेना ने बताया कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर महामहिम रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। 2020 में एक हवाई आपातकाल के दौरान अपने एलसीए तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए उन्हें सम्मान मिला था।

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया गया सफलतापूर्वक परीक्षण

नई दिल्ली (आरएनएस)। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का आज (08 दिसम्बर, 2021) ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से प्रातः 10:30 बजे सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 एमके -1 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस उल्लेखनीय उड़ान में विमान से लॉन्च की गई मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्व नियोजित गति प्रक्षेप पथ (ट्रजेक्टरी) का पालन किया।

यह लॉन्च ब्रह्मोस के विकास में एक प्रमुख उपलब्धि है। यह देश में वायु संस्करण ब्रह्मोस मिसाइलों के क्रमबद्ध उत्पादन की प्रणाली को उजागर करता है। रामजेट इंजन का मुख्य भाग स्थापित करने वाली प्रमुख एयरफ्रेम असेंबलियां भारतीय उद्योग द्वारा स्वेदशी रूप से विकसित की गई हैं। इन असेंबलियों में रामजेट ईंधन टैंक और वायु चालित (न्यूमैटिक) ईंधन आपूर्ति प्रणाली सहित गैर-धात्विक वायु फ्रेम सेक्शन शामिल हैं। परीक्षण के दौरान, संरचनात्मक अखंडता और कार्यात्मक प्रदर्शन प्रमाणित हुए हैं। ब्रह्मोस के वायु संस्करण का पिछला परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण फायरिंग पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), ब्रह्मोस, भारतीय वायु सेना और उद्योग की प्रशंसा की है।

ईडी ने केरल में पीएफआई के 4 ठिकानों पर छापेमारी की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार ठिकानों पर विदेशी फंडिंग से जुड़े एक मामले में छापेमारी की। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि ईडी को पीएफआई द्वारा विदेशी मार्गों से कथित तौर पर प्राप्त धन के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुए थे। केरल के कुछ लोग जो विदेश में रह रहे हैं, वे भी जांच के घेरे में हैं।

एक सूत्र ने कहा, जो लोग हमारे रडार पर हैं, उन्हें भी तलब किया जाएगा।

ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीएफआई के मोहम्मद साकिब ने कहा कि वे इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए अपडेट का इंतजार कर रहे है।

उन्होंने कहा कि हम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तस्वीर साफ होने के बाद हम टिप्पणी कर पाएंगे।

पीएफआई के एक अन्य अधिकारी सलीम ने कहा कि उन्हें चल रही चीजों के बारे में जानकारी नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, पीएफआई के चार सदस्य अतीक-उर-रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम को हाल ही में पिछले साल 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि हाथरस बलात्कार और हत्या मामले के बाद वे कथित तौर पर राज्य में दंगे भड़का रहे थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान चारों ने सरेंडर कर दिया था, और कबूल किया था कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव, जो कि पीएफआई की छात्र शाखा है, उसने उन्हें आर्थिक मदद की और कथित तौर पर राज्य में दंगा भड़काने में उनकी मदद की थी।

आरोप है कि रऊफ के विदेशी संबंध हैं जिसके जरिए दूसरे सदस्यों को पैसे भेजे जा रहे थे। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस मामले के आधार पर वर्तमान में मामला दर्ज किया था।

राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक किया प्रदान

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के राष्ट्रपतिरामनाथ कोविन्द ने आज (8 दिसंबर, 2021) महाराष्ट्र के मुंबईमें भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन से जुड़े सभी अधिकारियों और नाविकों को यह उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बधाई दी।उन्होंने कहा कि स्क्वाड्रन को मानक प्रदान करना हमारे देश के लिए इसके पूर्व और मौजूदा अधिकारियों व नाविकों की उनकी असाधारण सेवा का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया कि इस स्क्वाड्रन के पोतों को कई अभियानों में शामिल किया गया है। वे

मिशन आधारित तैनाती के जरिए हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं।वे ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में राजनयिक मिशन व समुद्री डकैती-विरोधी अभियान का भी संचालनकर रहे हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत एक समुद्री राष्ट है। हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ाने और हमारे राष्ट्रीय हितों व वाणिज्यिक आकांक्षाओं की रक्षा करने में भारतीय नौसेना की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यह एक बहुत संतुष्टि की बात है कि भारतीय नौसेना संकल्प और दृढ़ता के साथ हमारे व्यापक समुद्री हितों की सफलतापूर्वक रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के क्षेत्र से होकर गुजरता है।इसे देखते हुए न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए भी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे समुद्री पड़ोसी देश आजविश्व की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में देखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियां भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका तय करती हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इस क्षेत्र की अग्रणी नौसेनाओं में से एक के रूप मेंभारतीय नौसेना ने सभी क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के साथ हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिये वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। केन-बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ रुपये, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किया है। यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी तथा विश्व के सामने हमारी बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण का भी परिचय देगी। इस परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जायेगा। यह दाऊधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहर को जोड़ने, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिये पूरा किया जायेगा। परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी, लगभग 62 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा तथा 103 मेगावॉट पन बिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री पीएमएवाई-जी को मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक जारी रखने को दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)' को मार्च 2021 के बाद भी जारी रखने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी का विवरण इस प्रकार हैः-

2.95 करोड़ आवासों के कुल लक्ष्य के अंतर्गत शेष आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मौजूदा

मानदंडों के अनुसार मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक 'पीएमएवाई-जी'को जारी रखना।

ज़ पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय भार 2,17,257 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 1,25,106 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 73,475 करोड़ रुपये) है। नाबार्ड को ब्याज चुकाने के लिए 18,676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।

'ईबीआर'को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूरी योजना के वित्त पोषण का इंतजाम सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के जरिए करने के बारे में निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।

असम एवं त्रिपुरा को छोड़कर प्रत्येक छोटे राज्य यथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर को छोड़ सभी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक कोष के केंद्रीय हिस्से (2त्र के कुल प्रशासनिक कोष में से 0.3त्र) में से सालाना अतिरिक्त 45 लाख रुपये का प्रशासनिक कोष जारी करना, जो उक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए 1.70 प्रतिशत के प्रशासनिक कोष के अतिरिक्त होगा।

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (एनटीएसए) को वित्त वर्ष 2023-24 तक जारी रखना।

इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि 'पीएमएवाई-जी'के तहत 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त 'पक्के मकानों' के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

29 नवंबर 2021 तक पीएमएवाई-जी के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य में से 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है। यह अनुमान है कि 2.02 करोड़ आवास, जोकि एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची के लगभग बराबर है, 15 अगस्त 2022 की समय सीमा तक पूरे हो जाएंगे। इसलिए 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की आवश्यकता है।